सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

मिशन कर्मयोगी
वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश 1

1. मिशन कर्मयोगी का परिचय 2

2. क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास 7

3. क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निर्णयकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन 10

4. क्षमता निर्माण पहल 17

5. मंत्रालय के संगठनों का आई-गॉट पर एकीकरण और नामांकन 22

6. विषय वस्तु विकास और प्रत्यायन 28

7. क्षमता निर्माण गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन 35

8. प्रदर्शन मैट्रिक्स और परिणाम 38

9. सर्वोत्तम पद्धतियां- शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं का सम्मान 42

संक्षिप्तियां

ए.सी.बी.पी.	वार्षिक क्षमता निर्माण योजना
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
अमृत	अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
बी.एम.टी.पी.सी.	निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद
सी.बी.सी.	क्षमता निर्माण आयोग
सी.बी.यू.	क्षमता निर्माण इकाई
डे- एन.यू.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना - नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन
डी.डी.ए.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डी.एम.आर.ए.	दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी
एफ.आर.ए.सी.	फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटी, एंड कॉम्पिटेंसी
हडको	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आई-गॉट	इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग
आई.एफ.यू.	इंटरनल फ्रैकिंग यूनिट
के.डी.एल.एल.	कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब
एम.ओ.एच.यू.ए.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एन.बी.सी.सी.	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
एन.सी.आर.पी.बी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एन.सी.आर.टी.सी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
एन.आई.यू.ए.	राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
एन.पी.सी.एस.सी.बी.	राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम
पी.एम.ए.वाई. -एच.एफ़.ए.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सभी के लिए आवास
पी.एम.सी.	परियोजना प्रबंधन परामर्श इकाई
पी.एम.ए. स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि
आर.सी.यू.ई.एस.	क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटीज़ मिशन
टी.एन.ए.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन
यू.डी.	शहरी विकास
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय

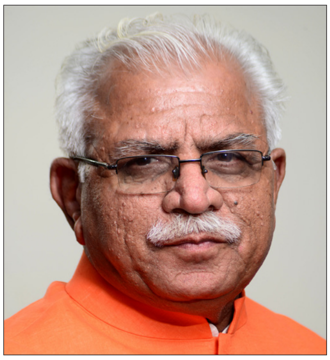

मनोहर लाल
केंद्रीय मंत्री
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

संदेश

लोक सेवकों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी पहल, मिशन कर्मयोगी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह पहल भविष्य के लिए ऐसी लोक सेवा तैयार करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो न केवल शासन की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि भारत के नागरिकों के लिए सेवा प्रदायगी के मानकों को भी बढ़ाती है।

माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार, मिशन कर्मयोगी ने लर्निंग इकोसिस्टम का एक ऐसा आधार तैयार किया है जो हमारे लोक सेवकों की आकांक्षाओं को 21वीं सदी के शासन की मांगों के अनुरूप बनाता है। पिछले वर्ष के दौरान, इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जिसमें इस मंत्रालय के 100% अधिकारियों को आई-गॉट में शामिल करना, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को बनाना और इसे कार्यान्वित करने के लिए इसके अनुरूप शिक्षण मार्ग तैयार करना और विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों के साथ साझेदारी का विस्तार शामिल है। यह रिपोर्ट आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की गई उपलब्धियों और उससे उत्पन्न प्रभावों को दर्शाती है।

जैसा कि हम आने वाले वर्ष में अपेक्षा करते हैं, हमारा उद्देश्य अपनी पहुंच को व्यापक बनाना, समावेशिता को अधिक बढ़ावा देना और प्रत्येक लोक सेवक में निरंतर सीखने और नैतिक शासन की भावना को प्रेरित करना हैं।

मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पहल की सफलता में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कर्मचारियों के निरंतर समर्पण और उनके अटूट सहयोग से मिशन कर्मयोगी लोक सेवा उत्कृष्टता में नए मानदंड स्थापित करेगा, जिससे हम माननीय प्रधानमंत्री के "विकसित भारत" के सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे।

तोखन साहू
राज्य मंत्री
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसे लोक सेवकों को आधुनिक शासन की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज, लोक सेवकों की भूमिका पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों से आगे बढ़ गई है, जिसके लिए अनुकूलनशीलता, विशेष ज्ञान और 21वीं सदी में शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी प्रगति की समझ की आवश्यकता है।

यह वार्षिक रिपोर्ट मिशन कर्मयोगी के प्रगति का प्रतीक और आगे की राह के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ दोनों के रूप में है। यह रिपोर्ट पिछले वर्ष हमारे मंत्रालय में की गई परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाती है, जिसमें नवीनता, सहयोग और नागरिक-केंद्रित शासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रयास एक नवीन भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले भविष्य के कार्यबल तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

यह प्रगति हमारे विभिन्न हितधारकों जैसे सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साझेदारों आदि के अमूल्य योगदान के बिना संभव नहीं होती। मिशन के उद्देश्यों को साकार करने में उनके समर्पण और टीमवर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैं उनके अटूट सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

इस रिपोर्ट में उल्लेखित उपलब्धियों के साथ, हम एक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन तंत्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। आइए हम सुशासन के सिद्धांतों से समाहित एक सक्रिय लोक सेवा तैयार करने की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखें जो एक प्रगतिशील और दूरदर्शी भारत के दृष्टिकोण के साथ अनुरूप हो।

श्रीनिवास आर कटिकिथाला
सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

प्राक्कथन

मुझे बहुत गर्व है कि मैं मिशन कर्मयोगी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है और एक सक्रिय, कुशल और सेवा-उन्मुख लोक सेवा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मिशन कर्मयोगी सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण में एक आदर्श बदलाव के रूप में कार्य करता है, जो लोक सेवकों को आधुनिक शासन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सजग और कुशल बनाता है।

पिछला वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धियों का और सीखने का वर्ष रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के शुरुआत के बाद आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर सीखना, कौशल वृद्धि और उत्तम प्रदर्शन-आधारित विकास हर सरकारी अधिकारी के कार्य का अभिन्न अंग बन गया है। हमने विभिन्न व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं पर भौतिक/ऑफ़लाइन कार्यशालाओं के माध्यम से मंत्रालय में सीखने का एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में मंत्रालय में व्यापक आउटरीच, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, पहलों और सर्वोत्तम पद्दतियों तथा प्रभावशाली साझेदारियों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने सामूहिक रूप से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के दृष्टिकोण को सफल बनाया है।

मिशन कर्मयोगी की प्रगति हमारे अधिकारियों के समर्पण और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, जो न केवल नए कौशल और दक्षताओं को अपना रहे हैं, बल्कि नागरिकों की सेवा करने के लिए दक्षता और जवाबदेही के साथ नई प्रतिबद्धता भी अपना रहे हैं। यह पहल केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है; यह एक व्यापक ढांचा है जो लोक सेवा में नैतिक शासन, जवाबदेही और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

मैं इस विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ – जिनमें हमारे मंत्रालय की टीमें, साझेदार संगठन और अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस मिशन में पूरे मन से भाग लिया है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमारा ध्यान मिशन कर्मयोगी की नींव को मजबूत करने, इसके संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करने और प्रभावी शासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके निरंतर विकास पर रहेगा।

कार्यकारी सारांश

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई एक व्यापक मानव संसाधन सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा को विश्व स्तरीय, नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा में बदलना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से लैस सिविल सेवक तैयार करना है, जो भारतीय संस्कृति के लोकाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हों, ताकि जनभागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित सर्वोच्च प्राधिकरण है, जो नीतियां बनाता है, कार्यक्रम प्रायोजित करता है, विभिन्न स्तरों पर कार्यनीतियों का समन्वय करता है और देश में आवास और शहरी मामलों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी करता है।

मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-सक्षम सिविल सेवा विकसित करने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न क्षमता-निर्माण पहलों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक निर्धारित क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) की स्थापना की गई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के 100% अधिकारी और संबंधित कार्यालय सफलतापूर्वक डिजिटल प्रणाली से जुड़ गए हैं।

अधिदेश के अनुसार, मंत्रालय ने अक्तूबर, 2023 में वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) विकसित और लॉन्च की, जिसे क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा सुगम बनाया गया। एसीबीपी एक दस्तावेज है जिसमें मंत्रालय के लिए विशिष्ट, मापनीय और समयबद्ध क्षमता निर्माण हस्तक्षेप शामिल हैं। मंत्रालय विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से एसीबीपी को लगन से लागू करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों की प्रासंगिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण अवसरों और सहायता तक पहुँच हो। मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों ने सीबीसी से प्रत्यायन प्राप्त किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है और उनकी परिचालन क्षमताएँ बढ़ी हैं। उल्लेखनीय उपलब्धि जिसमें नए जॉइनर्स के लिए 'अपने मंत्रालय को जाने' मॉड्यूल का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय के कार्यों और उद्देश्यों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की मिशन कर्मयोगी पहलों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एक निर्धारित वेबपेज लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सात पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जिनमें से चार पहले ही आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो चुके हैं। यह आई-गॉट पर अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन की सक्रिय रूप से निगरानी करता है, सीखने और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने और उनकी सराहना करने के लिए हर महीने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पहचानता है।

कुल मिलाकर, इन पहलों ने मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की क्षमता निर्माण और पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्रालय निरंतर सीखने और पेशेवर विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1

परिचय

मिशन कर्मयोगी

सितंबर 2020 में, भारत सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एन.पी.सी.एस.सी.बी.) शुरू किया, जिसे 'मिशन कर्मयोगी' के नाम से जाना जाता है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में शासन की उभरती जरूरतों को संबोधित करना है। एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के रूप में स्थापित, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे राष्ट्र की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए सही कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण से लैस हों। प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में एक शीर्ष निकाय द्वारा संचालित, इस कार्यक्रम को नागरिक-केंद्रित, चुस्त और उत्तरदायी सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आधुनिक शासन की जटिलताओं को नेविगेट कर सके।

1.1 पृष्ठभूमि

सिविल सेवाएँ शासन तंत्र की रीढ़ हैं, जो नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समय के साथ, सिविल सेवकों पर रखी गई माँगें लगातार जटिल होती जा रही हैं, जिसके लिए उन्हें न केवल पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों में बल्कि डिजिटल शासन, सतत विकास और नागरिक जुड़ाव जैसी समकालीन चुनौतियों में भी निपुण होने की आवश्यकता है। इन माँगों को पूरा करने के लिए, सिविल सेवकों को अपने कौशल और दक्षताओं को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता है। मिशन कर्मयोगी एक कार्यनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवकों के पास बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेजी से जागरूक और सक्रिय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल और दक्षताओं का सही मिश्रण हो।

1.2 मिशन कर्मयोगी के उद्देश्य

मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सिविल सेवाओं में सुधार के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नियम-आधारित प्रणाली से अधिक भूमिका-आधारित, योग्यता-संचालित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है। मिशन में छह मुख्य स्तंभ शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर सिविल सेवकों के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी सक्षम कार्यढांचे की आवश्यकता है जो चुस्त, नागरिक-केंद्रित हो और भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो।

मिशन कर्मयोगी के छह स्तंभ

ग्राफ 1: मिशन कर्मयोगी के छह स्तंभ

मिशन कर्मयोगी - भविष्य के लिए कुशल सिविल सेवा का निर्माण करना

-उचित व्यवहार, कौशल और ज्ञान को नए भारत के विज़न में शामिल करना

योग्यता आधारित क्षमता निर्माण

भारत का अपना सिविल सेवा योग्यता कार्यढांचा

भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की साझा समझ

जवाबदेही और पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठ **मूल्यांकन** के माध्यम से

प्रभाव का पैमाना

एक वैश्विक उदाहरण - पहले वर्ष में 30 लाख एवं दीर्घकाल में 2 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता

नागरिक केंद्र/ केंद्रित

नागरिक केन्द्रितता (सम्मानपूर्ण बातचीत, समस्या समाधान क्षमता)
विषय वस्तु विशेषज्ञता और व्यवहारिक परिवर्तन

व्यापार करने में आसानी

आर्थिक विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाना और सेवाएं

जीवन में आसानी

नागरिकों को समय पर और प्रभावी सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की क्षमता

ग्राफ 2: मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य और दृष्टिकोण

1.3 शासन

और संगठनात्मक संरचना

मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन के लिए एक संरचित और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह एक पदानुक्रमित ढांचे द्वारा संचालित होता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर कई हितधारक शामिल होते हैं। शीर्ष निकाय कार्यनीतिक दिशा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रमुख मंत्रालयों, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। नियमित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रम के उद्देश्य कुशलतापूर्वक पूरे हों और क्षमता निर्माण के प्रयास शहरी शासन की उभरती जरूरतों के अनुरूप हों।

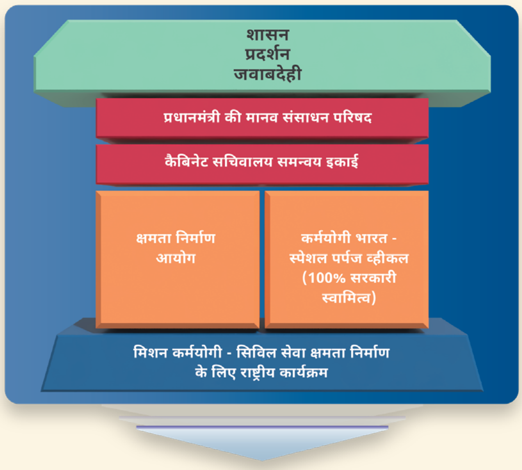

प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद (पीएमएचआरसी) - क्षमता निर्माण सुधारों को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने वाली शीर्ष निकाय

कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई - प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी और योजनाओं की देखरेख करना

क्षमता निर्माण आयोग प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करेगा, साझा संकाय और संसाधन बनाएगा एवं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का पर्यवेक्षण करेगा

कर्मयोगी भारत-स्पेशल पर्पज व्हीकल-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म-आईजीओटी कर्मयोगी का स्वामित्व और संचालन करेगा और विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।

ग्राफ 3: मिशन कर्मयोगी की संस्थागत संरचना

1.4 आई-गॉट का उपयोग करने के लाभ

आई-गॉट क्षमता निर्माण के लिए कई लाभ प्रदान करता है:

- **कार्यनीतिक साझेदारियां:** अग्रणी संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, उन्नत कार्यप्रणाली और उद्योग विशेषज्ञता तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **सतत वित्तपोषण:** सरकारी और निजी क्षेत्र के योगदान से युक्त एक मजबूत वित्तपोषण मॉडल कार्यक्रम की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **लागत-प्रभावी शिक्षण:** यह मंच व्यापक, लागत-प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक व्यक्तिगत कार्यक्रमों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **सतत सीखने की संस्कृति:** यह सिविल सेवकों के बीच आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **मान्यता और प्रोत्साहन:** प्रमाणपत्र/मान्यता सिविल सेवकों को सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।

ग्राफ 4: मिशन कर्मयोगी के लाभ

1.5 मिशन कर्मयोगी की सफलता के लिए अवसरों का द्वार खोलना

मिशन कर्मयोगी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने के लिए, मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विकास और सुधार के कई अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है:

- **परिवर्तन को अपनाना:** सिविल सेवकों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन कार्यनीतियों के माध्यम से नए प्लेटफार्मों और प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **डिजिटल पहुंच बढ़ाना:** दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- **विकास की मानसिकता को बढ़ावा देना:** सिविल सेवाओं में नवाचार और व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सीखने और योग्यता-आधारित प्रदर्शन की संस्कृति का विकास करना।
- **पाठ्यक्रम प्रासंगिकता सुनिश्चित करना:** सिविल सेवकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, सहभागिता और प्रभाव को बढ़ाना।
- **भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और मान्यता तंत्र बनाना।
- **प्रशिक्षण प्रयासों का विस्तार:** मंत्रालय के विविध और व्यापक कार्यबल तक प्रभावी ढंग से पहुँचने के लिए सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण पहलों का विस्तार करना।
- **कार्यालयों में सामंजस्य स्थापित करना:** क्षमता निर्माण प्रयासों को संरेखित करने और एकीकृत प्रगति हासिल करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संगठनों में समन्वय को मजबूत करना।

2

क्षमता निर्माण
का विकास

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मिशन कर्मयोगी पहल में अग्रणी रहा है, तथा शहरी शासन के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी क्षमता निर्माण पहलों का नेतृत्व कर रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के विकास में सफलतापूर्वक काम किया है और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

2.1 भूमिकाएं, गतिविधियां और दक्षताएं तैयार करने की रूपरेखा (एफ़.आर.ए.सी.)

एफआरएसी को मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित किया गया था, जो मंत्रालय/विभाग/संगठन के भीतर आवश्यक भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं की पहचान करता है। कार्यशालाओं की एक श्रृंखला और मंत्रालय के कर्मियों के साथ आमने-सामने की चर्चाओं के माध्यम से, प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए) आयोजित किया गया, जिससे एक विस्तृत रूपरेखा तैयार हुई जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के भीतर प्रत्येक भूमिका के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को रेखांकित करती है।

2.1.1. योग्यता ढांचा और अंतर मूल्यांकन

मिशन कर्मयोगी का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, जो कि योग्यता ढांचे पर आधारित है, पारंपरिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और योग्यता सवर्धन की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

नियमित योग्यता अंतर मूल्यांकन सिविल सेवकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करके व्यक्तिगत सीखने की यात्रा को सक्षम बनाता है।

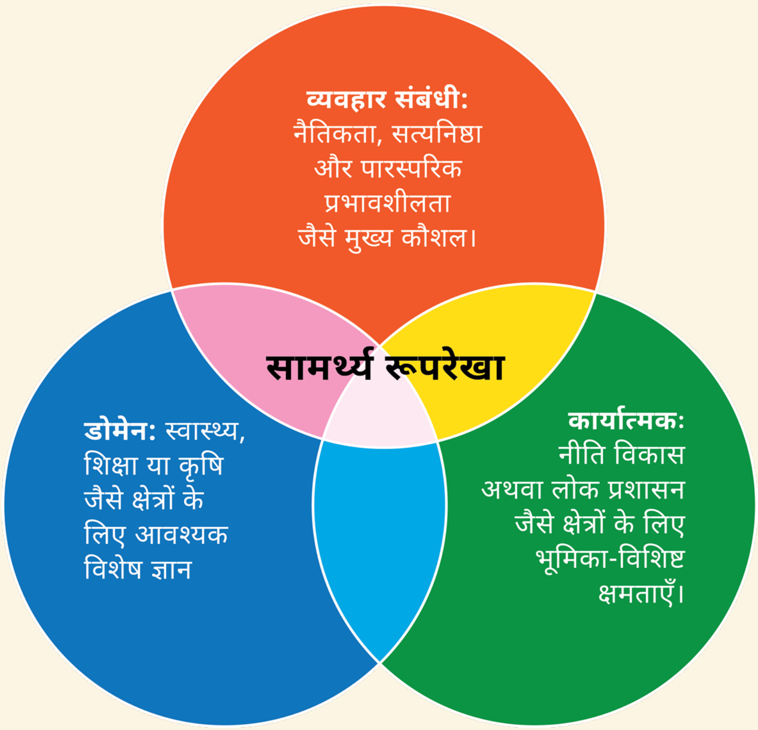

ग्राफ 5: मिशन कर्मयोगी के तहत सामर्थ्य की रूपरेखा

2.2 वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ए.सी.बी.पी.)

प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टी.एन.ए.) से मिली जानकारी के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसीबीपी विकसित किया है। ए.सी.बी.पी. व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन-विशिष्ट दक्षताओं में मंत्रालय की क्षमता-निर्माण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक कार्यनीतिक रोडमैप प्रदान करता है। यह एक परिवर्तनशील दस्तावेज है जिसे उभरती चुनौतियों और शहरी शासन की विकसित प्रकृति के आधार पर लगातार अपडेट किया जाना है। ए.सी.बी.पी. को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्षमता वृद्धि एक स्थायी, सतत प्रक्रिया है जो मंत्रालय के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है।

2.3 निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र

- **कौशल** बढ़ाने के लिए भौतिक कार्यशालाएँ और शिक्षण सत्र आयोजित करना।
- **आई-गॉट प्लेटफ़ॉर्म डेटा** का उपयोग जुड़ाव और सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- **व्यक्तिगत और विभागीय प्रदर्शन** का आकलन करने के लिए प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग किया जाता है।

2.3.1. क्षमता निर्माण इकाई (सी.बी.यू.डी.)

क्षमता निर्माण प्रयासों की स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव (सीबीयूडी) की अध्यक्षता में एक समर्पित सीबीयू की स्थापना की है, जिसमें 04 अन्य डी.एस. और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह इकाई क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है, उनकी प्रगति की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनका मूल्यांकन और जवाबदेही हो।

- योग्यता ढांचे, विषय वस्तु विकास आदि को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित।
- इसमें विभिन्न प्रभागों और मिशनों के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं।
- वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एस.सी.बी.पी.) को एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करता है।

2.3.2. मिशनों/प्रभागों/संगठनों के लिए नोडल अधिकारी

- प्रत्येक प्रभाग/मिशन/संगठन में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- ये अधिकारी संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, प्रगति पर नज़र रखते हैं और मिशन कर्मयोगी के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं।
- कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सी.बी.यू. द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3

क्षमता निर्माण के विकास के लिए निर्णयकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन

3.1 माननीय मंत्री द्वारा मान्यता

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 13 नवंबर 2024 को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डबल्यू.) के दौरान उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई। मंत्री ने क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए उनके असाधारण प्रयासों और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

चित्र 1 और 2: माननीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डबल्यू.) की कार्यनिष्पादन समीक्षा

चित्र 3: राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह की सोशल मीडिया उपस्थिति

3.2 अर्बन लर्नथॉन 2.0 में 'अपने मंत्रालय को जाने' मॉड्यूल का टीज़र रोलआउट

8 जनवरी 2025 को, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने आधिकारिक तौर पर अर्बन लर्नथॉन 2.0 के दौरान 'अपने मंत्रालय को जाने' मॉड्यूल का टीज़र लॉन्च किया। यह व्यापक शिक्षण पहल (अपने मंत्रालय को जाने' मॉड्यूल) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और प्रमुख कार्यों के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों के बीच ज्ञान बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

यह पहल क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार के प्रति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे हितधारक समुदाय को अधिक जानकारी प्राप्त होगी और शहरी विकास में मंत्रालय की भूमिका के बारे में गहन समझ विकसित होगी।

चित्र अर्बन लर्नथॉन 2.0 के दौरान 'अपने मंत्रालय को जाने' मॉड्यूल का टीज़र रोलआउट

3.3 शहरी शासन को सशक्त बनाना: शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) की क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला और वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एस.सी.बी.पी.) का शुभारंभ

अक्टूबर, 2023 में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण आयोग (सी.बी.सी) के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को सशक्त बनाने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह कार्यक्रम, देश भर में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिध्द हुई। कार्यशाला ने यूएलबी को सेवा प्रदायगी, परिचालन दक्षता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में सुधार के लिए विचारों और कार्यनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

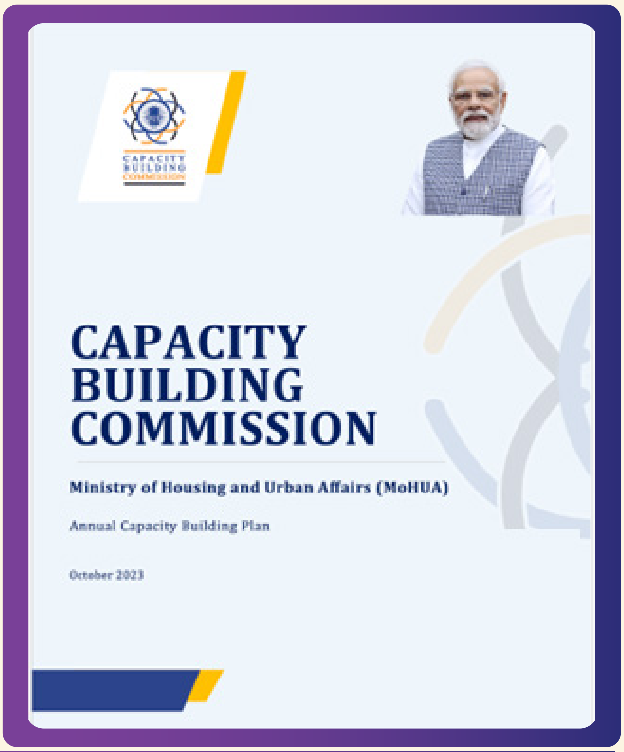

चित्र 4: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का वार्षिक क्षमता निर्माण योजना

3.4 शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) की क्षमता निर्माण: सी.बी.सी. और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.) के साथ साझेदारी

- शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को आई-गॉट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने की राष्ट्रव्यापी पहल के संबंध में क्षमता निर्माण आयोग (सी.बी.सी.) और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एन.आई.यू.ए.) के साथ 15 मार्च, 2024 को हुई चर्चा के बाद, 19 सितंबर, 2024 को एक कार्यनीतिक बैठक बुलाई गई।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास आर कटिकिथाला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीबीसी और एनआईयूए के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। चर्चाओं में मंत्रालय के अधिकारियों का आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, जिसमें प्रत्येक को कम से कम पांच कोर्स पूरे करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, बैठक में शहरी स्थानीय निकायों के लिए सीबीसी के मॉडल को अपनाकर और एनआईयूए की चल रही पहलों का लाभ उठाकर क्षमता निर्माण को मजबूत करने की आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की कार्यनीति पर जोर दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

चित्र 5: शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण के लिए सी.बी.सी. के साथ सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई

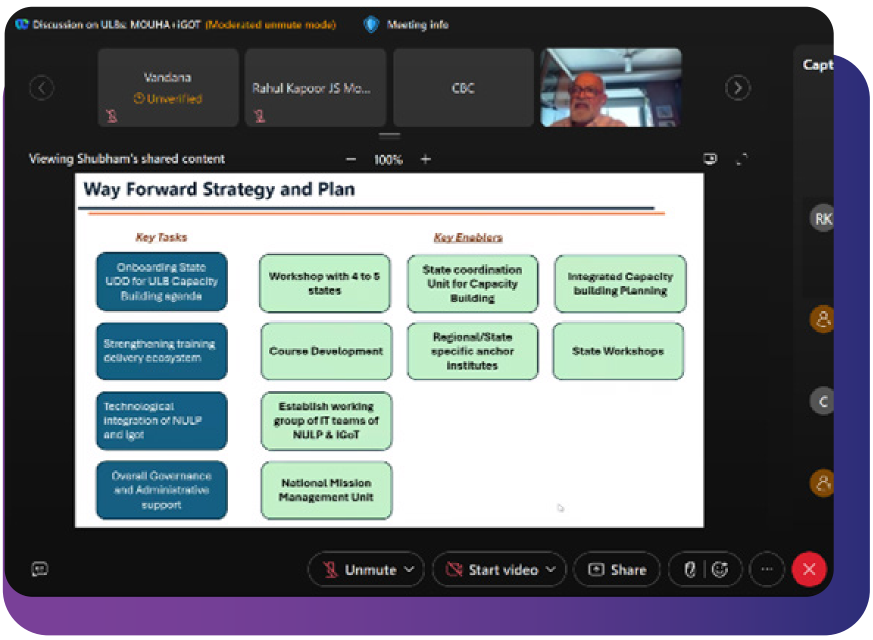

चित्र 6: यू.एल.बी. की क्षमता निर्माण हेतु सी.बी.सी. के साथ वी.सी. आयोजित

3.5 वरिष्ठ अधिकारियों की राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह में भागीदारी

19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास आर कटिकिथाला ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक शिक्षण सत्र आयोजित किया। अधिकारियों ने एक संरचित शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें आई-गॉट पर पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए 4 घंटे निर्धारित किए गए।

चित्र 7: वरिष्ठ अधिकारियों का चार घंटे का शिक्षण सत्र (i)

चित्र 8: वरिष्ठ अधिकारियों का चार घंटे का शिक्षण सत्र (ii)

चित्र 9: सोशल मीडिया की उपस्थिति और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डबल्यू.) हेतु समाचार पत्र के विशेष संस्करण का शुभारंभ

3.6 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) के साथ साझेदारी में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण

❖ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) के साथ साझेदारी में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना चाहता है। यह पहल नेतृत्व को बढ़ाने, सेवा प्रदायगी में सुधार करने और शहरी शासन को मजबूत करने के लिए डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। पाँच साल की अवधि में, कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित यूएलबी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना है। अपेक्षित परिणामों में बेहतर नेतृत्व और कौशल, बढ़ी हुई शासन उत्पादकता, बेहतर नगरपालिका सेवाएँ और सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है।

❖ हाल ही में, 9 दिसंबर, 2024 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

❖ इस दूरदर्शी साझेदारी का उद्देश्य उच्च ऋण पात्रता वाले यू.एल.बी. जैसे की भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, ठाणे, बैंगलोर, एनडीएमसी (नई दिल्ली) और सूरत जैसे शहरों की क्षमता का निर्माण करना है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित है:

- **प्रशासन और शासन को बढ़ाना:** प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- **कार्यनीतिक योजना:** शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप बनाना।
- **वित्तीय स्थिरता:** मजबूत निवेश और परिचालन योजनाएं विकसित करना।
- **दीर्घकालिक विजन:** शहर की आकांक्षाओं के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को संरेखित करना। अगले तीन वर्षों में यह पहल प्रभावशाली बदलाव लाएगी, जिससे शहरों को अपनी क्षमता को अनलॉक करने और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

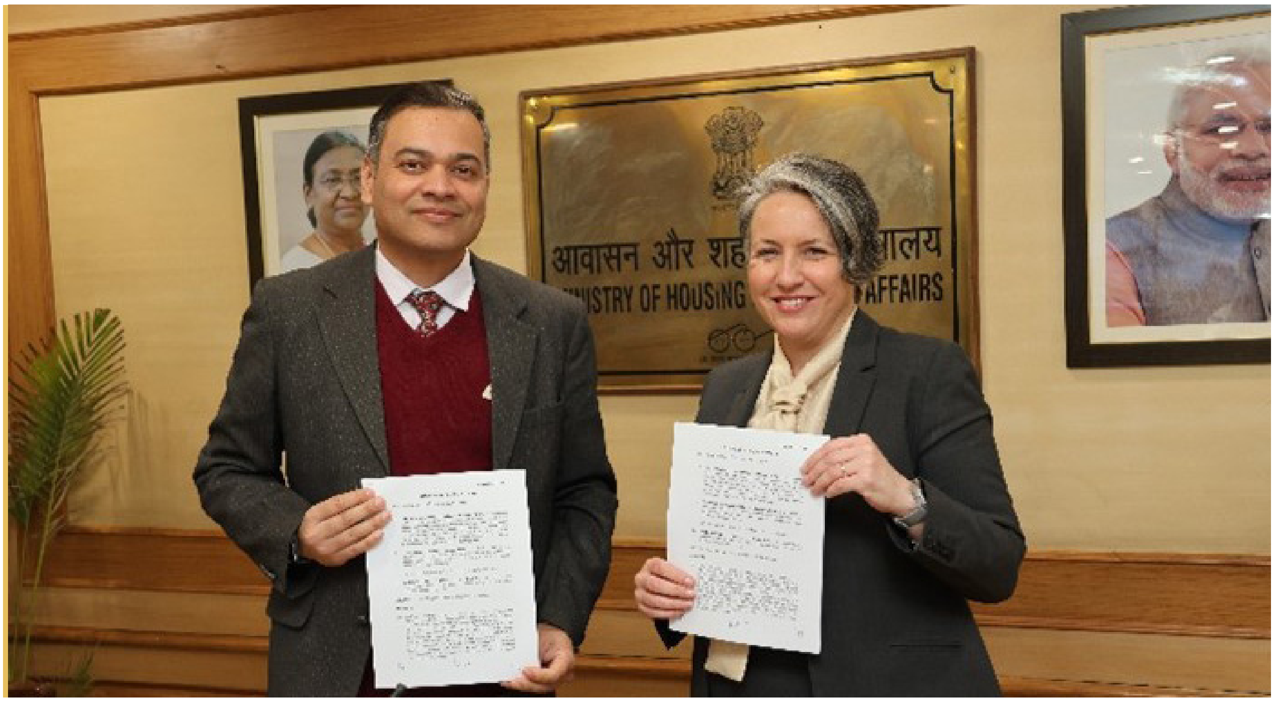

चित्र 10: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और आई.एफ.सी. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

4

क्षमता निर्माण पहल

4.1 कल्याणकारी पहल: "कर्मयोगियों की योगशाला" कार्यशालाएं

वर्ष 2023 में आयोजित "डेस्क योग और कल्याण" कार्यशालाओं के माध्यम से 20 से अधिक प्रभागों और संगठनों के लगभग 450 अधिकारियों को तनाव प्रबंधन और कल्याण के बारे में अवगत कराया गया। इन सत्रों ने मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और उत्पादकता को बढ़ावा दिया

चित्र 11: कर्मयोगी की योगशाला कार्यशालाएं

4.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता में वृद्धि

4.2.1. उभरती प्रौद्योगिकी पर कार्यशालाएं

डिजिटल परिवर्तन के महत्व को समझते हुए, 27 सितंबर और 17 अक्टूबर, 2023 को वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (डब्ल्यू.आई.टी.पी.) के सहयोग से जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन सत्रों ने अधिकारियों को एआई अनुप्रयोगों और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तकनीकों से अवगत कराया।

चित्र 12 उभरती तकनीकियों पर कार्यशालाएं

4.2.2. सतर्कता जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डब्ल्यू.)

- मंत्रालय में अगस्त से नवंबर 2024 तक सतर्ककता जाागरूकता अभियान चलाया गया। मंत्राालय ने आई.एस.टी.एम. के पूर्व प्रशिक्षकों के माध्यम से, कार्यालय प्रक्रिया और आचरण नियम, नैतिकता और शासन और खरीद फरोख्त पर आठ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एन.आई.सी. टीम ने साइबर स्वच्छता और सुरक्षा पर पांच प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला में मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

- कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं पर आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर 23 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम अनिवार्य किए गए।
- एस.बी.एम. प्रभाग के अधिकारियों और सी.पी.एच.ई.ई.ओ. के सलाहकारों ने अपनी टीमों के साथ, स्थायी पद्धतियों के अनुरूप स्वच्छता और जल प्रबंधन में अधिकारियों की डोमेन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे के सत्र में भाग लिया।
- लगभग 215 अधिकारियों ने डोमेन विषय क्षेत्रों में अपनी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का लाभ उठाया।

चित्र 13: सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान आचरण नियमों पर प्रशिक्षण सत्र

चित्र 14: सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान खरीद फरोख्त पर प्रशिक्षण सत्र

चित्र 15: सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान नैतिकता और शासन पर प्रशिक्षण सत्र

सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण सत्र

चित्र 17: सोशल मीडिया उपस्थिति

4.2.3. आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर सत्र

आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई ने एस.बी.एम. 2.0 के विभिन्न घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जयपुर के शहरी स्थानीय निकायों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए 13 नवंबर 2024 को जयपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आई.एफ.यू.-मिशन कर्मयोगी के विषय विशेषज्ञ ने एस.बी.एम. दिशानिर्देश 2.0 पर एक सत्र दिया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एस.बी.एम. घटक के कार्यान्वयन पर जयपुर के यू.एल.बी. के विभिन्न स्तर के अधिकारियों की जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया। इन सत्रों से लगभग 50 लोगों को लाभ हुआ।

चित्र 18: जयपुर में आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई के सहयोग से एस.बी.एम. परिचालन दिशानिर्देश 2.0 पर सत्र

चित्र 19: जयपुर में आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई के सहयोग से एस.बी.एम. परिचालन दिशानिर्देश 2.0 पर सत्र

4.2.4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 18 नवंबर 2024 को सी.आई.एस.सी.ओ. के साथ समन्वय में ए.आई. और साइबर सुरक्षा पर ज्ञान-साझाकरण सत्र का आयोजन किया है। कार्यशाला की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (सी.बी.यू.डी.) ने की और इसमें विभिन्न प्रभागों और मिशनों के लगभग 40 अधिकारी और परामर्शदाता शामिल हुए।

चित्र 20: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यशाला

चित्र 21: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यशाला

4.3 दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी का फील्ड दौरा

शहरी परिवहन प्रभाग के 25 अधिकारियों ने 2023 और 2024 में 03 अध्ययन यात्रा के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी का दौरा किया। इन दौरों से मेट्रो रेल प्रणाली, परिचालन उत्कृष्टता और सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिली, जिससे तकनीकी कौशल और परिचालन संबंधी जानकारी को बढ़ावा मिला।

चित्र 22: संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा डी.एम.आर.ए. का दौरा

चित्र 23: अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण अनुभव

4.4 मिशन की डिजिटल दृश्यता को बढ़ावा देना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मिशन कर्मयोगी के लिए एक निर्धारित वेब पेज लॉन्च किया गया है।

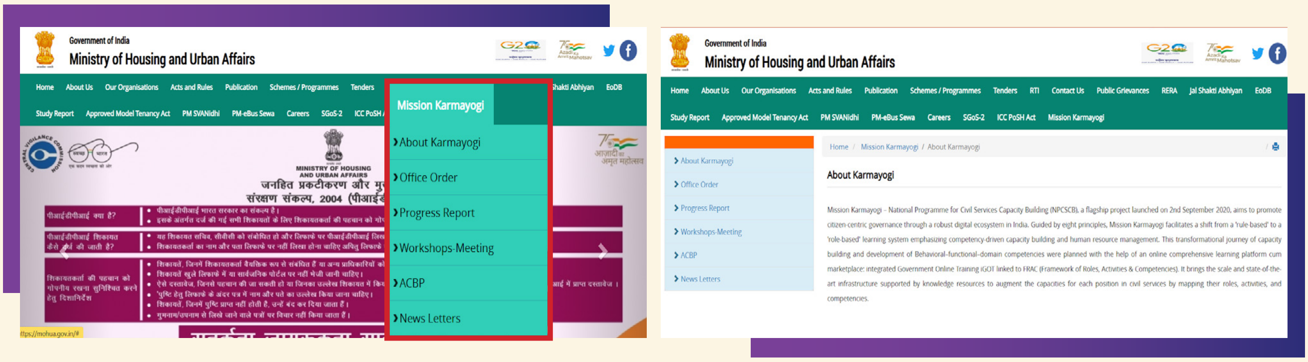

चित्र 24: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मिशन कर्मयोगी के लिए समर्पित पेज

4.5 आई-गॉट के लिए तकनीकी सहायता और शिकायत निवारण

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण से संबंधित तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए आंतरिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है जिससे कि कर्मचारियों का आई-गॉट पर प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुँचना सुगम हुआ है।

5

आई-गॉट पर

मंत्रालय के संगठनों का एकीकरण और नामांकन

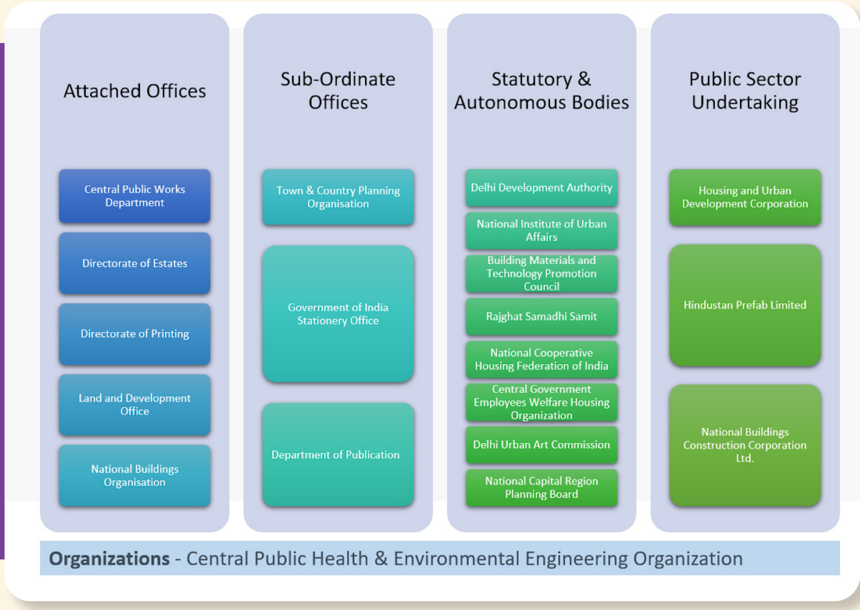

ग्राफ 6: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न संगठन

मई 2024 में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय के संबंधित संगठनों (एन.आई.यू.ए.एन.सी.आर.पी.बी., डी.यू.ए.सी., बी.एम.टी.पी.सी., टी.सी.पी.ओ., सी.पी.डब्ल्यू.डी., एच.यू.डी.सी.ओ., जी.आई.एस.ओ., एन.सी.आर.टी.सी., डी.डी.ए., एन.बी.सी.सी., एच.एस.सी.सी., एन.बी.ओ. और एच.पी.एल.) के साथ भौतिक, ऑनलाइन और फिजिकल प्रारूप में कुल 14 कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इन सत्रों का उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को मिशन कर्मयोगी उद्देश्यों के साथ संरेखित करना था।

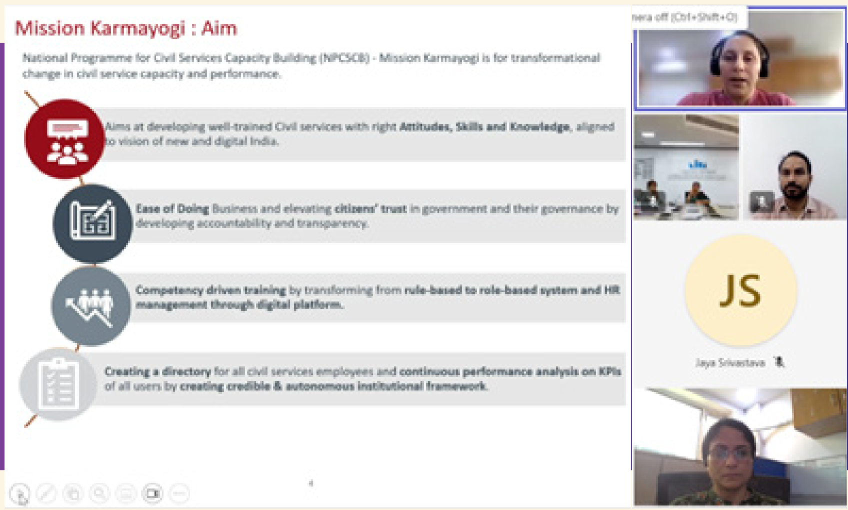

चित्र 25: संगठनात्मक ऑनबोर्डिंग पर एन.आई.यू.ए. के साथ आयोजित वी.सी.

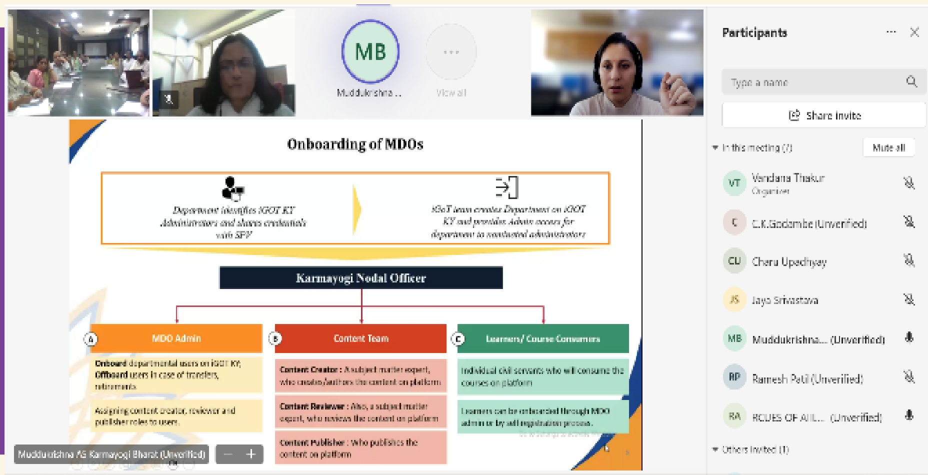

चित्र 26: संगठनात्मक ऑनबोर्डिंग पर आर.सी. यू.ई.एस.-मुंबई के साथ आयोजित वीसी

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संगठनात्मक ऑनबोर्डिंग कार्य का विवरण

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

7 मई

संगठन

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

11

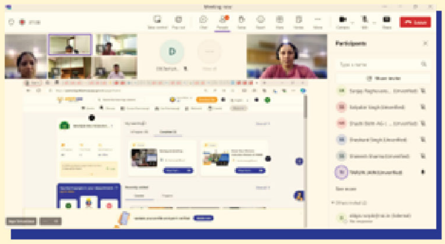

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

14 मई

संगठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

12

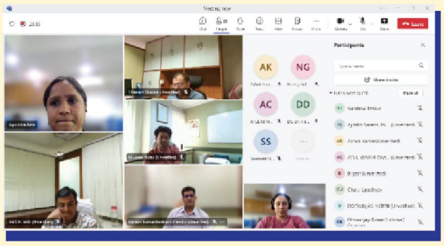

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

16 मई

संगठन

दिल्ली नगर कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) और निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

37

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

17 मई

संगठन

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन (टी.सी.पी.ओ.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

32

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

03 जून

संगठन

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

08

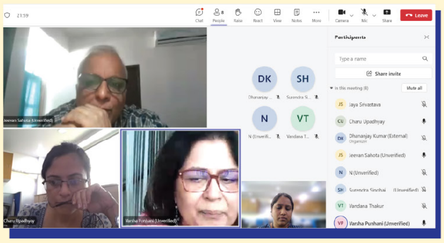

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

05 जून

संगठन

भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय (जी.आई.एस.ओ.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

26

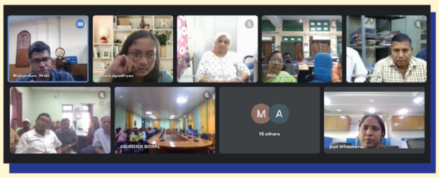

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

06 जून

संगठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन.सी.आर.टी.सी.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

05

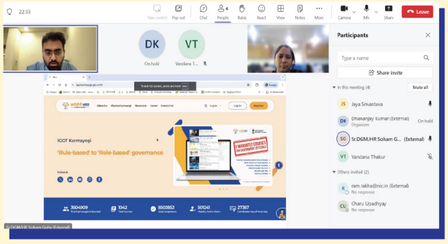

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

19 जून

संगठन

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

14

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

19 जून

संगठन

एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड

प्रतिभागियों की कुल संख्या

05

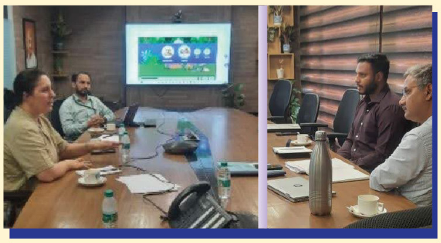

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

21 जून

संगठन

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

20

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

11 जुलाई

संगठन

हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.एस.सी.सी.) एन.बी.सी.सी. की सहायक कंपनी

प्रतिभागियों की कुल संख्या

16

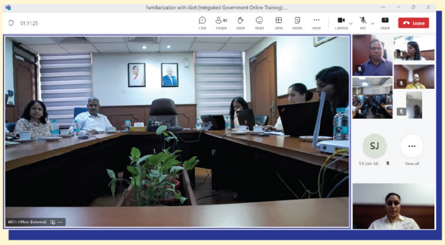

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

16 जुलाई

संगठन

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

15

वी.सी. और एफ.जी.डी. की तारीख

24 जुलाई

संगठन

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल.)

प्रतिभागियों की कुल संख्या

08

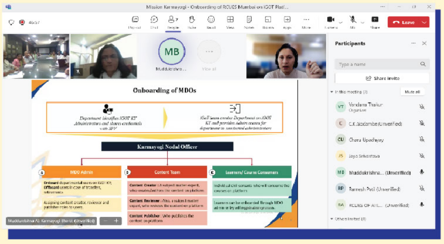

6

विषय वस्तु विकास और प्रत्यायन

6.1 अपने मंत्रालय को जानिए – इंडक्शन ई-लर्निंग कोर्स

संगठनात्मक समझ को और विकसित करने के लिए मंत्रालय के मिशन के साथ संरेखित करते हुए सी.बी.सी. के सहयोग से “अपने मंत्रालय को जानें” शिक्षण मॉड्यूल का विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय के अधिकारियों को विभागीय कार्यों से परिचित कराना है। पाठ्यक्रम में कुल 04 मॉड्यूल शामिल हैं।

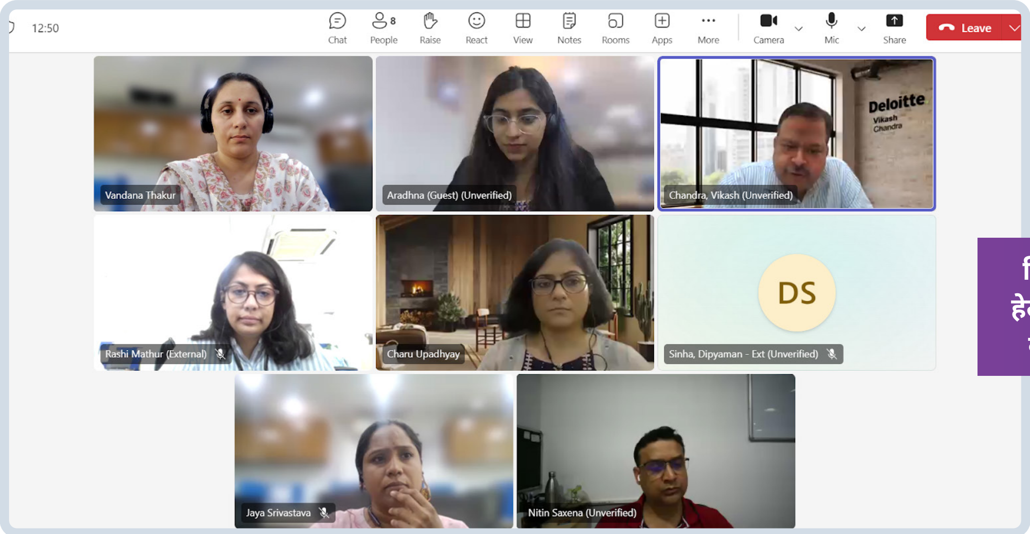

चित्र 27: कंटेंट डेवलपमेंट हेतु एस.सी.एम.-पी.एम.सी. के साथ आयोजित वीसी

6.2 एस.बी.एम. 2.0 ई-लर्निंग मोड्यूल

❖ आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई ने “स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएमयू 2.0) - एस.डब्ल्यू.एम. पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश” पर एक पाठ्यक्रम विकसित किया है।

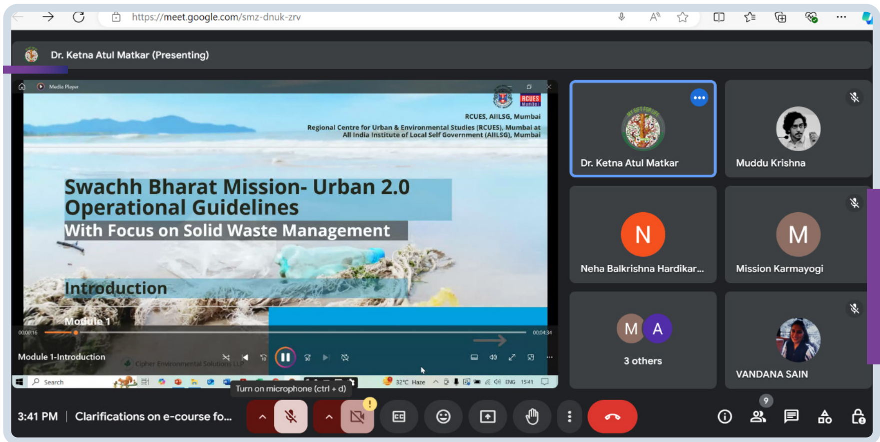

चित्र 28: कंटेंट डेवलपमेंट हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और आर.सी.यू.ई.एस मुंबई के बीच वीसी

❖ आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की और से आई-गॉट पर विषय वस्तु विकास करने के प्रयासों में सहायक रहा है। इन सत्रों में सामग्री मानकों, गुणवत्ता मानदंडों और भूमिका-विशिष्ट पाठ्यक्रमों के सृजन पर चर्चा की गई, जिन्हें मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया।

6.3 ई-लर्निंग मोडयूल के लिए के.डी.एल.एल. के साथ सहयोग

- एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्तपोषित कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब (के.डी.एल.एल.) के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के छह प्रभागों - अमृत, पी.एम. स्वनिधि, एन.यू.एल.एम., दिल्ली प्रभाग, शहरी परिवहन, स्मार्ट सिटीज मिशन और आवास - ने आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली ई-सामग्री के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
- उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण अनुभव प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई बैठकें आयोजित की गईं कि विषय-वस्तु सरकारी कर्मियों की कौशल वृद्धि आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

6.3.1. डे-एन.यू.एल.एम. पर इंडक्शन कोर्स

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एन.यू.एल.एम.) पर एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। डे-एन.यू.एल.एम. को गरीबी में रहने वाले शहरी परिवारों को कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसरों और जरूरी आवास और सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

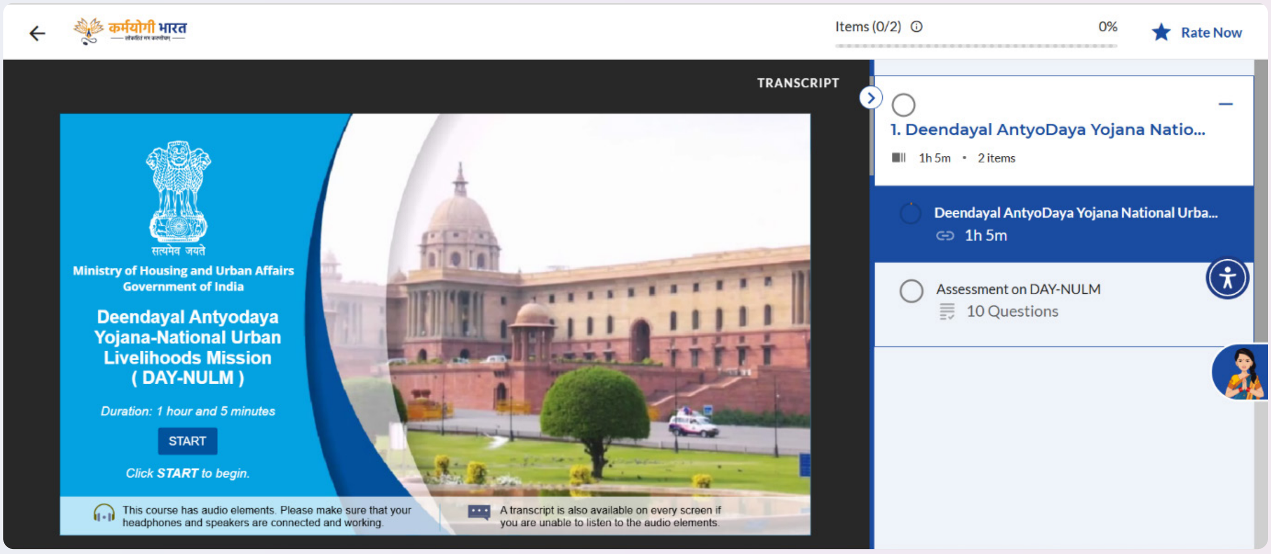

चित्र 29: आई-गॉट हेतु विकसित डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम. पाठ्यक्रम

6.3.2. इंडक्शन कोर्स पी.एम. स्वनिधि

मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना (पी.एम. स्वनिधि योजना) पर एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम इस योजना की जानकारी प्रदान करता है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए पी.एम. स्वनिधि योजना जैसी प्रमुख नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

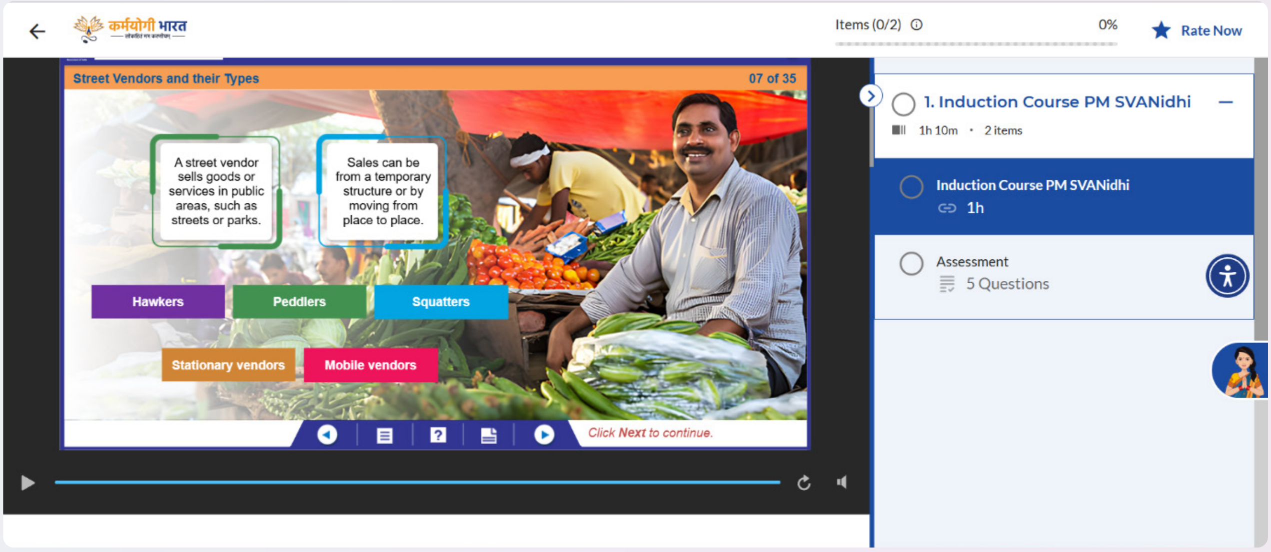

चित्र 30: आई-गॉट हेतु विकसित पी.एम. स्वनिधि पाठ्यक्रम

6.3.3. आई.सी.सी.सी. के माध्यम से शहरों में शहरी सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन

आई.सी.सी.सी. के माध्यम से शहरों में शहरी सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन नामक पाठ्यक्रम एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी.) और शहरी शासन को बढ़ाने में इसकी भूमिका को स्पष्ट करता है। नगरपालिका सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और केंद्रीकृत निगरानी और डेटा विश्लेषण के माध्यम से निर्णय लेने में सुधार करने की उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को आईसीसीसी के उद्देश्यों और संरचना को जानने के लिए प्रेरित करेगा।

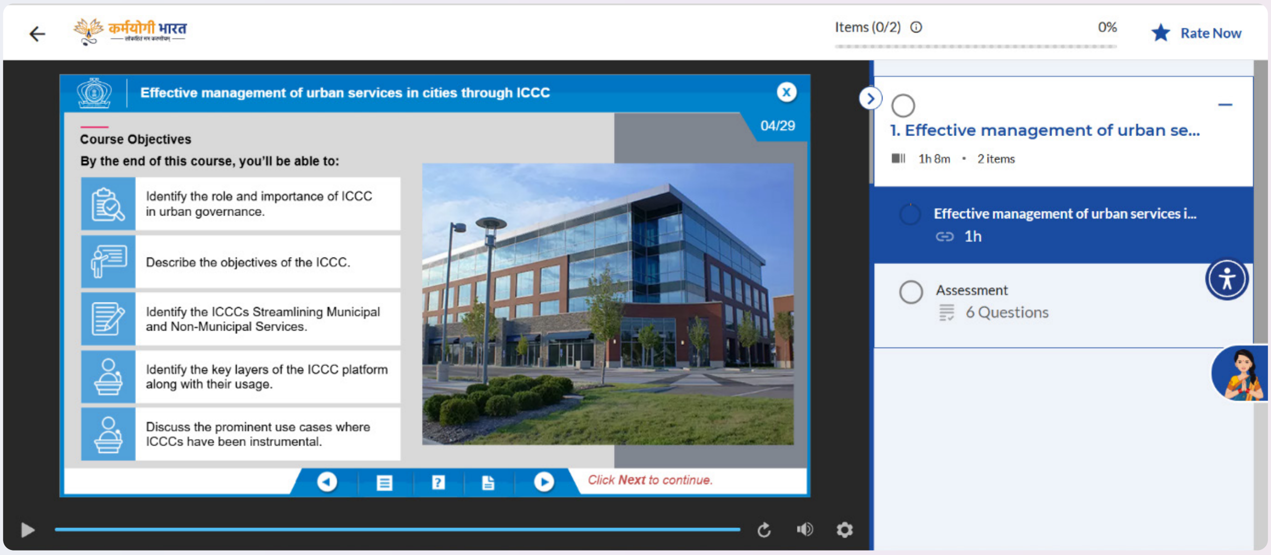

चित्र 31: आई-गॉट हेतु विकसित एस.सी.एम. का आई.सी.सी.सी. पाठ्यक्रम

6.3.4. मेट्रो रेल नीति 2017

मेट्रो रेल नीति 2017 पाठ्यक्रम में मास रैपिड ट्रांजिट (एम.आर.टी.) प्रणाली की बुनियादी बातों को शामिल किया गया है। इसमें अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग की मुख्य चरणों की रूपरेखा दी गई है और परिवहन प्लानिंग में वैकल्पिक विश्लेषण की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इसके द्वारा प्रतिभागी उपलब्ध विभिन्न मेट्रो रेल विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे और मेट्रो परियोजना नियोजन के विभिन्न चरणों के बारें में जानेंगे।

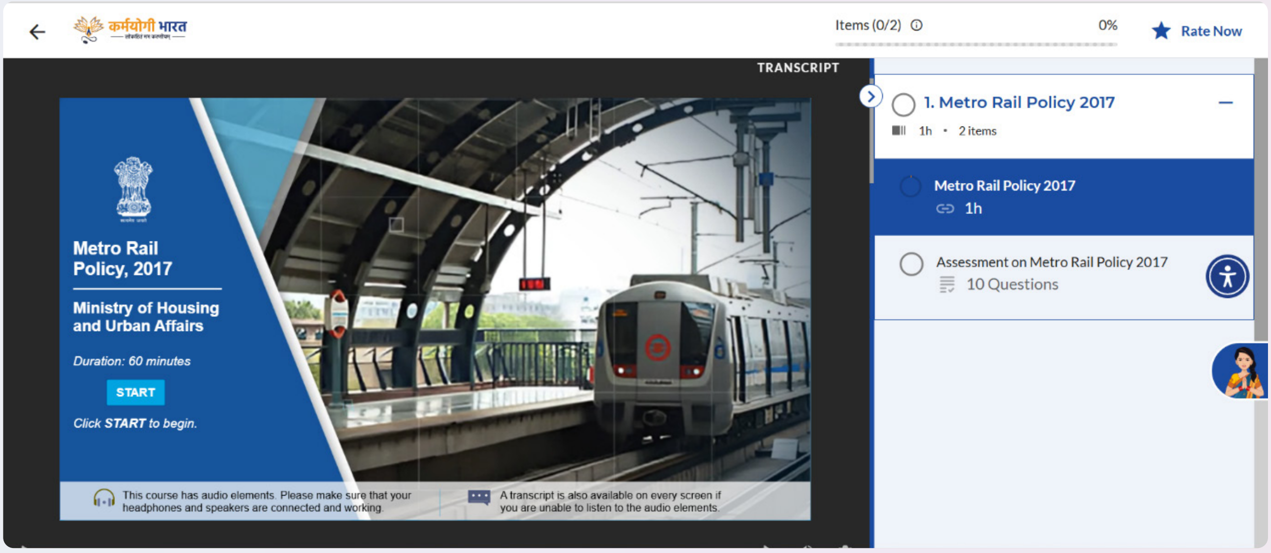

चित्र 32: आई-गॉट हेतु विकसित मेट्रो रेल नीति पाठ्यक्रम

6.3.5. प्रयुक्त जल प्रबंधन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त जल प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण और पुन: उपयोग कार्यनीतियों पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में जल चक्रीयता, अपशिष्ट जल शोधन, उन्नत शुद्धिकरण तकनीक और कीचड़ प्रबंधन सहित कई विषयों को शामिल किया गया।

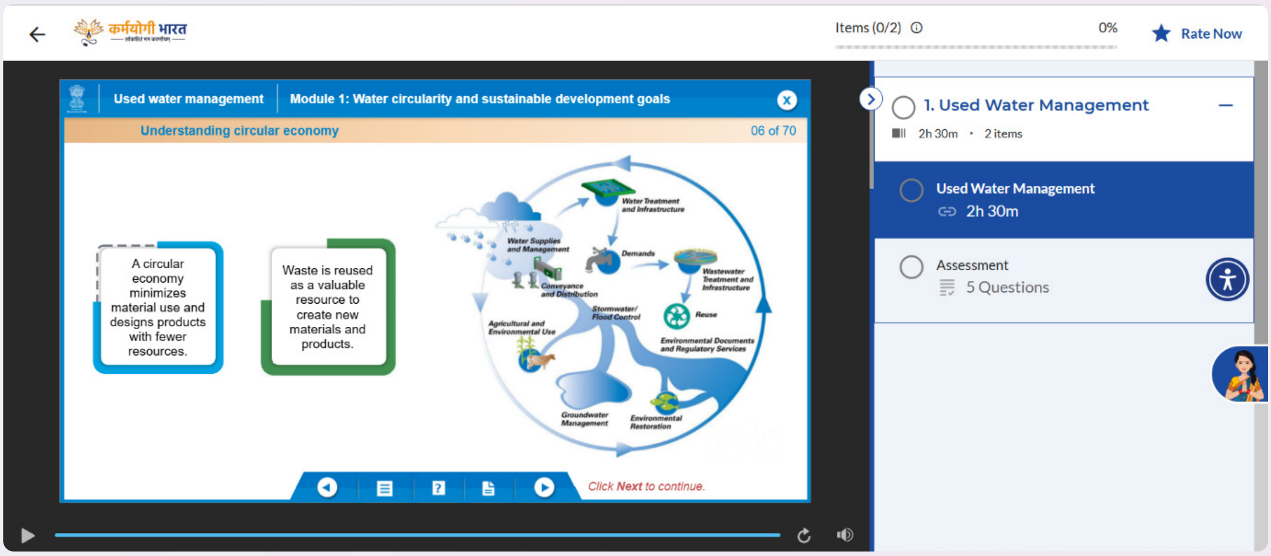

चित्र 33: आई-गॉट हेतु विकसित प्रयुक्त जल प्रबंधन पाठ्यक्रम

6.4 आई-गॉट पर स्वच्छता–ही-सेवा का शुभारंभ

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए 30 सितंबर 2024 को आई-गॉट पर स्वच्छता ही सेवा पाठ्यक्रम शुरू किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एक व्यवस्थित शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पहलों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए सशक्त बनाना है। यह पहल देश भर में साफ-सफाई अभियान-स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार के साथ संरेखित है।

चित्र 34: आई-गॉट हेतु एस.बी.एम. द्वारा विकसित स्वच्छता-ही-सेवा पाठ्यक्रम

6.5 क्षमता निर्माण सम्मेलन : मान्यता और डिजी मंथन 2.0

12 अगस्त, 2024 को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानो का सम्मेलन आयोजित किया गया और “डिजी-मंथन 2.0” डिजिटल पाठ्यक्रम पहल की शुरुआत की गई। 2024 तक डीएमआरए, आरसीयूईएस लखनऊ और आरसीयूईएस-मुंबई ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (एन.एस.सी.एस.टी.आई.) फ्रेमवर्क के तहत मान्यता प्राप्त कर ली है।

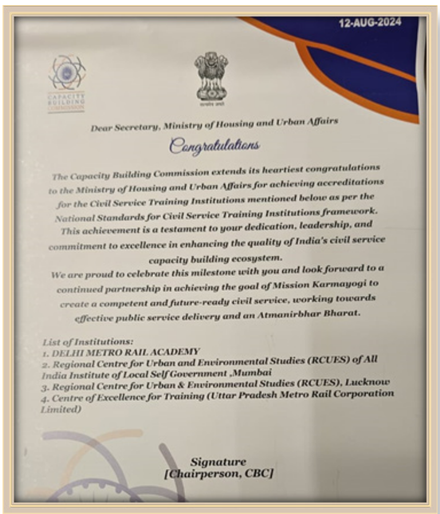

12-AUG-2024

Dear Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs

Congratulations

The Capacity Building Commission extends its heartiest congratulations to the Ministry of Housing and Urban Affairs for achieving accreditations for the Civil Service Training Institutions mentioned below as per the National Standards for Civil Service Training Institutions framework. This achievement is a testament to your dedication, leadership, and commitment to excellence in enhancing the quality of India's civil service capacity building ecosystem.

We are proud to celebrate this milestone with you and look forward to a continued partnership in achieving the goal of Mission Karmayogi to create a competent and future-ready civil service, working towards effective public service delivery and an Atmanirbhar Bharat.

List of Institutions:
1. DELHI METRO RAIL ACADEMY
2. Regional Centre for Urban and Environmental Studies (RCUES) of All India Institute of Local Self Government ,Mumbai
3. Regional Centre for Urban & Environmental Studies (RCUES), Lucknow
4. Centre of Excellence for Training (Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited)

Signature
[Chairperson, CBC]

चित्र 35: सी.एस.टी.आई. कन्वेंशन 2024 – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रत्यायन रोल

चित्र 36: सी.एस.टी.आई. कन्वेंशन 2024 – संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रत्यायन प्राप्त करते हुए

चित्र 37: सी.एस.टी.आई. कन्वेंशन 2024 – आर.सी.यू.ई.एस.-मुंबई द्वारा प्राप्त प्रत्यायन प्रमाणपत्र

CAPACITY BUILDING COMMISSION

Certificate of Accreditation

The training institute **Regional Centre for Urban and Environmental Studies (RCUES) of All India Institute of Local Self Government ,Mumbai** is accredited as **Good/अति उत्तम** under the Capacity Building Commission's National Standards.

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance with the National Standards. The accreditation needs to be renewed before the expiry date by the training institution following the due process of assessment.

Accreditation granted on 28/05/2024 is valid until 27/05/2026

Secretary
Capacity Building Commission

Chairperson
Capacity Building Commission

Certificate No.
APP/23/N00233

चित्र 38: आर.सी.यू.ई.एस.-मुंबई द्वारा प्राप्त प्रत्यायन प्रमाणपत्र

7

क्षमता निर्माण

गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन

7.1 क्षमता निर्माण इकाई (सी.बी.यू.) की बैठकें

सी.बी.यू. की बैठकें सितंबर और अक्टूबर 2023, जनवरी और मई 2024 में संयुक्त सचिव (सी.बी.यू.डी.) की अध्यक्षता में आयोजित की गईं, जहाँ आने वाले वर्ष के वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के उद्देश्यों और समयसीमा को अंतिम रूप दिया गया।

चित्र 39: सी.बी.यू. की बैठक

7.2 सहयोगात्मक डैशबोर्ड और प्रगति की ट्रैकिंग

पारदर्शिता और वास्तविक समय अपडेट सुनिश्चित करने के लिए, सीबीसी द्वारा विकसित वार्षिक क्षमता निर्माण योजना कार्यान्वयन डैशबोर्ड की समीक्षा 14 फरवरी, 2024 को निर्देशक सी.बी.यू.डी., आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक सत्र में की गई। यह डैशबोर्ड पहलों और उपलब्धियों की निरंतर निगरानी में सहायता करता है।

चित्र 40: कर्मयोगी भारत और क्षमता निर्माण आयोग के साथ बैठक

7.3 नोडल अधिकारियों की बैठक

संयुक्त सचिव, सी.बी.यू.डी.,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 27 फरवरी, 2024 और 6 अगस्त, 2024 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी मिशनों, प्रभागों और संगठनों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा में आई-गॉट प्लेटफ़ॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण, पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षाओं के अनुपालन और “अपने मंत्रालय को जानें” मॉड्यूल और इंडक्शन कोर्स जैसी पहलों के संबंध में प्रगति अपडेट पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चित्र 41: नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक

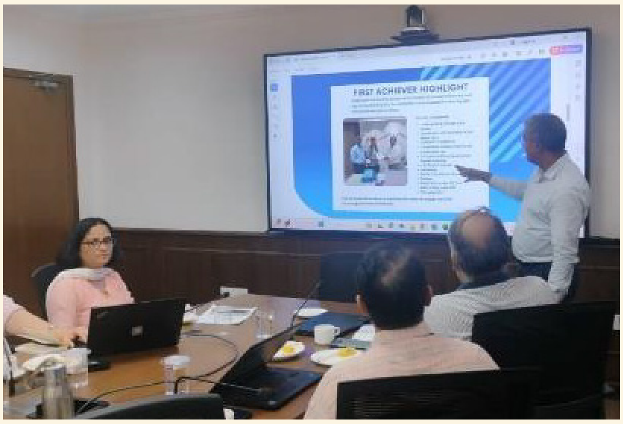

चित्र 42: एन.बी.सी.सी. द्वारा क्षमता निर्माण पर प्रस्तुति

7.4 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक

दिनांक 8 जुलाई, 2024 को संयुक्त सचिव (सी.बी.यू.डी.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में मिशन कर्मयोगी की समीक्षा की गई जिसमें इन बिन्दुओं को शामिल किया गया।

- सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (एन.एस.सी.एस.टी.आई.) के लिए राष्ट्रीय मानक आधारित मान्यता
- गुणवत्ता सुधार योजनाएँ, आई-गॉट ऑनबोर्डिंग और पाठ्यक्रम विकास। डी.एम.आर.ए., आर.सी.यू.ई.एस. मुंबई और लखनऊ को उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.) प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चित्र 43: सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक

8

प्रदर्शन मैट्रिक्स और परिणाम

भौतिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ

कार्यात्मक दक्षताएँ:12

सतर्कता जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह, एन.एल.डब्ल्यू. के तहत – 150 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया

डोमेन दक्षताएँ: 3

वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी और सिस्को के सहयोग से – 100 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया

व्यवहारिक दक्षताएँ;

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के 20 से अधिक प्रभागों के लिए योग कार्यशालाएँ (लगभग 450 अधिकारियों को शामिल किया गया)

प्रशिक्षण दौरे (डी.एम.आर.ए.)

03

ऑनलाइन शिक्षा:

- राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डब्ल्यू.) के दौरान –
  - वरिष्ठ अधिकारियों (संयुक्त सचिव व उच्च अधिकारी) के लिए 04 घंटे के शिक्षण सत्रों के साथ 01 कार्यशाला
  - 86 अधिकारियों ने 4 घंटे से अधिक का आई-गॉट पाठ्यक्रम पूरा किया।
  - 70 अधिकारियों ने आई-गॉट पर लाइव वेबमिनार में भाग लिया
  - 447 ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे किए गए।

- निदेशक से एम.टी.एस. स्तर तक के लगभग 100 अधिकारियों को उनके सराहनीय प्रदर्शन और आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिए सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

8.1 आई-गॉट में अधिकारियों का शामिल होना

- मंत्रालय ने आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों का 100% पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे सभी मिशनों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित हुई। चल रहे प्रयासों में अधीनस्थ कार्यालयों को शामिल करना और प्रत्येक इकाई के लिए अनुकूलित क्षमता निर्माण योजनाओं के निरुपण में सहायता करना शामिल है।

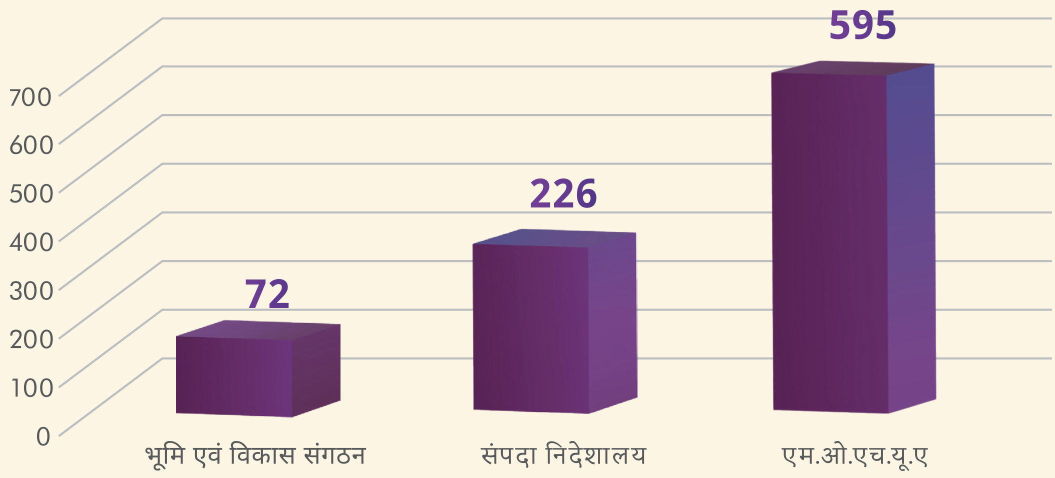

ग्राफ 7: आई-गॉट पर पंजीकृत अधिकारियों की संख्या

- पिछले दो वर्षों के ऑनबोर्डिंग के रुझान निम्नलिखित चित्र में प्रस्तुत किए गए हैं।

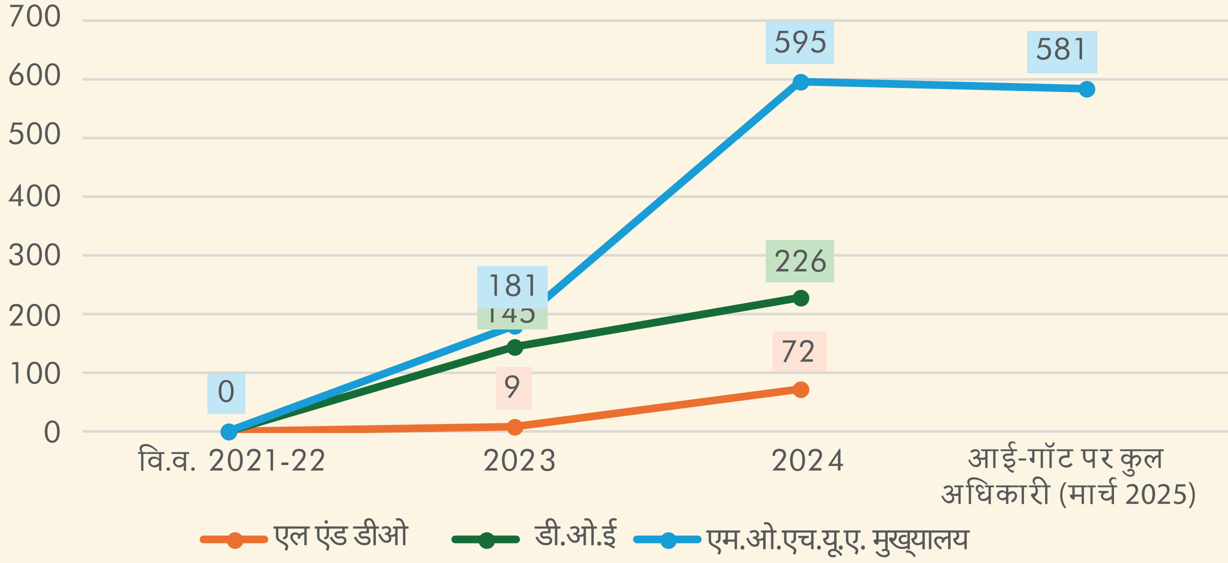

ग्राफ 8: मंत्रालय में आई-गॉट पंजीकरण का रुझान

8.2 सतर्कता जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान प्रदर्शन

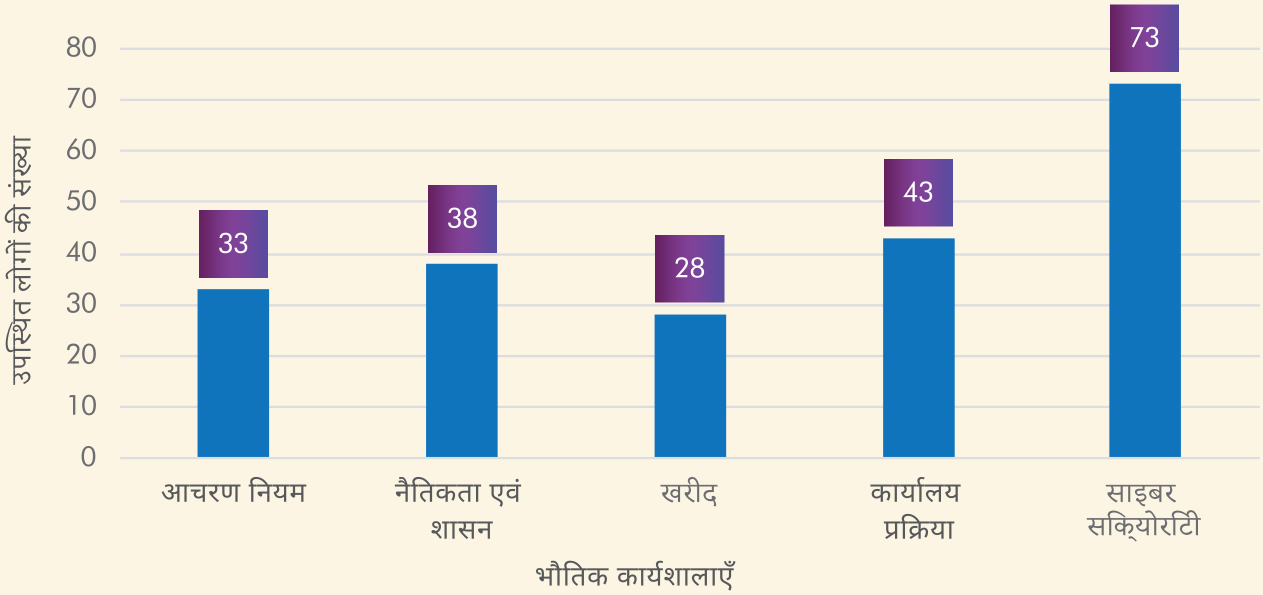

ग्राफ 9: सतर्कता जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान प्रशिक्षण सत्रों में अधिकारियों की उपस्थिति

9

सर्वोत्तम अभ्यास

आई-गॉट पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का सम्मान

आई-गॉट (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) जैसे ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का सम्मान कर्मचारियों को प्रेरित करता है, सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है और निरंतर विकास के महत्व को उजागर करता है।

9.1 शीर्ष प्रदर्शन कर्ताओं के मासिक चयन के लिए पात्रता मानदंड

- आई-गॉट पर पंजीकृत सभी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 6 घंटे का प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।
- सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने एक कैलेंडर माह के भीतर अधिकतम घंटों का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।

चित्र 44: मंत्रालय में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रमाण पत्र

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार